शहर से बाहर होंगे सरकारी कार्यालय

शहर से बाहर ले जाने का राज्य सरकार का फैसला पटना सहित सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों को जमीन अधिग्रहण करने का आदेश

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

सरकारी कार्यालय शहर से बाहर जाएंगे। शहरों के विस्तार और आबादी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले चरण में राजधानी पटना के साथ ही आठ अन्य प्रमंडलीय मुख्यालयों का चयन किया गया है। पटना में 60 और अन्य आठ शहरों में 50-50 एकड़ जमीन अधिग्रहण का निर्देश दिया गया है। सरकार की इस योजना से गया, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा और मुंगेर के दिन बहुरने वाले हैं। इससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कारण पुराने कार्यालयों पर बढ़ता दबाव कम होगा। साथ ही इन शहरों के विस्तारीकरण को भी दिशा मिलेगी। सरकारी आवास भी जरूरत के हिसाब से उसी भूखंड पर बनेंगे। यातायात का बढ़ता दबाव भी कम होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सरकारी कार्यालयों को शहर से बाहर ले जाने के लिए नौ शहरों से संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि बाहरी क्षेत्र में लेकिन शहर के निकट होगी। एप्रोच रोड का होना जरूरी है। सरकार का मानना है कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से नये-नये कार्यालयों को खोलना जरूरी हो गया है। वर्तमान कार्यालयों में भीड़ बढ़ गई है जिससे आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। नई योजना से हर शहर में बेतरतीब ढंग से हो रहे निर्माण पर भी रोक लगेगी। जाहिर है जिन दिशाओं में नये कार्यालय स्थापित होंगे उसी दिशा में नई आबादी भी बढ़ेगी। विस्तार की दिशा तय हो जाएगी तो नये निर्माण भी योजनाबद्ध ढंग से होंगे।

> राज्य के हर प्रमुख शहर में आबादी बढ़ती जा रही है। इससे आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर नये बनने वाले सरकारी कार्यालय शहर से बाहर होंगे। इससे शहरों के विकास को नई दिशा मिलेगी
>
> **दीपक कुमार** प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

क्या होगी प्रक्रिया

- भू अर्जन का प्रस्ताव जिलों से आयेगा
- जमीन के लिए अनुमानित राशि का ब्योरा देना होगा
- अगले वित्तीय वर्ष में भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

चालू होंगी बाजार समितियां

पटना। बाजार समितियां फिर चालू की जाएंगी पर इनका स्वरूप बदला होगा। वहां सुविधाएं भी अधिक होंगी। बिहार देश में पहली बार यह नया प्रयोग करने जा रहा है। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने किसानों के हित के इस बड़े फैसले की घोषणा की। इसके साथ 130 करोड़ की लागत से पोटही में बनने वाले राज्य के पहले टर्मिनल मार्केट के भी जल्द ही चालू होने की घोषणा उन्होंने की।

देखें पेज-6